DRAFT SUGGESTED BY LAW SECTION OF ENC OFFICE

कार्यालय मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर
दूरभाष 0731–2541498 फैक्स 0371–2536576
) Email-cephedind@nic.in.,cephedind@gmail.com (

क्रमांक /सा./आर.–/डी–/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि/25 इंदौर, दिनांक / /2025

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन क्रमांक 17625/2021 (श्री साबिर खान पिता नूर मोहम्मद खान बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास के अधिनस्थ कार्यरत रहे श्री साबिर खान, सेवानिवृत्त कार्यभारित टेलीफोन अटेंडेंट के द्वारा रिट पिटीशन में चाही गयी सहायता के संबंध में पात्रता का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री साबिर खान पिता नूर मोहम्मद खान सेवानिवृत्त कार्यभारित टेलीफोन अटेंडेंट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 17625/2021 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न साहयता चाही गई थीः–

(a)That. This Hon'ble court may be pleased to issue a writ in the nature of Mandamust of Issue any order or directions for giving benefit of I& II Kramonnati revised the pay & pension accordingly and paid the entire arrears with interest.

(b)To direct the Respondents to grant the petitioner's time bound promotions/Ist & IInd Kramonnati.

(c) To allow this petition with costs.

(d)To grant any other relief, which this Hon'ble court may deem fit in the facts and circumstances of the case, in favor of petitioner.

(2) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

Order passed by this Court dated 23/2/20215 in W.P No.876/2015 has not been challenged in any Court of law and the same has become final. Benefit under said order has already been granted to other similarly situated employees. Considering the aforesaid, the present petition is disposed off directing the respondents to consider the case of the petitioner in the light of the order dated 23/2/2015 passed in W.P No.876/2015 and pass reasonable and speaking order within period of 60 days from the date of filing of the order passed today.

With the aforesaid, present petition is disposed off.

(3) रिट याचिका क. 17625/2021 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 11.04.2025 प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास (म.प्र.)
–

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने बावत्।

विषय में निवेदन है कि प्रार्थी को नियुक्ति कार्यभारित टेलीफोन अटेंडेंट के पद पर जून 1993 में की गई जिसके अनुसार प्रथम क्रमोन्नती 2005 एवं द्वितीय कमोन्नती 2017 के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नती का लाभ प्रदान करने एवं एरियर का भुगतान करने का कष्ट करें।

(4) अंतिम रूप से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण :–

माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 17625/2021 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के परिपालन में, श्री साबिर खान (सेवानिवृत्त कार्यभारित टेलीफोन अटेंडेंट) को कार्यभारित वाहन चालकों के समान 12 वर्ष एवं 24 वर्षो की सेवा उपरांत, प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता का निर्धारण किया जाना है । उक्त निर्धारण, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा **रिट याचिका क्रमांक 876/2015 (श्याम सुन्दर उपाध्याय एवं 15 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2015** के प्रकाश में किया जाना है ।

(5) न्यायालयीन निर्णय में उल्लेखित न्यायदृष्टांत का विवरण :–

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 876/2015 (श्याम सुन्दर उपाध्याय एवं 15 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2015 के प्रकाश में किया जाना है ।

इस संबंध में लेख है कि **''श्याम सुन्दर उपाध्याय''** प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2015 में रिट अपील क्रमांक 866/2009 (**म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम तेजूलाल यादव**) में पारित निर्णय का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 के माध्यम से कार्यभारित स्थापना के मात्र वाहन चालक पद पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु लागू किए गए 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के उपरांत दो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभं, कार्यभारित स्थापना के सभी पदों के कर्मचारियों को पाने की पात्रता है।

(6) रिट याचिका के माध्यम से प्रस्तुत दावे के सम्बन्ध में पात्रता का निर्धारण :–

यदि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा **रिट याचिका क्रमांक 876/2015 (श्याम सुन्दर उपाध्याय एवं 15 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2015** पर विचार किया जावे तो यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी को इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर प्रथम 12 वर्ष की सेवा उपरांत प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान एवं अगले 12 वर्ष की सेवा उपरांत द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता आती है। पूर्व में इस निर्णय के परिपालन में विभागीय याचिकाकर्ता कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ स्वीकृत भी किये गये है किन्तु यह पाया गया है कि पूर्व में जानकारी के अभाव में **''विलंब, अवधि बीत जाने एवं मौन सहमति – स्वीकृति ''** के तथ्यों को विचारण में नहीं लिया गया था।

वर्तमान में विभाग के पास उपलब्ध **''विलंब, अवधि बीत जाने एवं मौन सहमति – स्वीकृति ''** से संबंधित न्यायलयीन दृष्टांतो के मद्देनजर, याचिकाकर्ता कर्मचारी के अभ्यावेदन दिनांक 11.04.2025 का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है:–

(अ) याचिकाकर्ता का प्रकरण त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने से सम्बन्ध रखता है किन्तु प्रथम रिट याचिका सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष 07 माह पश्चात् दायर की गई है :–

याचिकाकर्ता कर्मचारी का प्रकरण त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने से सम्बन्ध रखता है तथा इस सम्बन्ध में Cause Of Action सेवा में रहने के दौरान, अंतिम वेतन प्राप्त करने तक लगातार उत्पन्न होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **M.R. Gupta v. Union of India and Others, (1995) 5 SCC 628** में पारित निर्णय में निम्नानुसार लेख है :–

> So long as the employee is in service, a fresh cause of action would arise every month when they are paid their salary on the basis of a wrong computation made contrary to the rules.

याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा अपने कार्यभारित स्थापना के पूरे लगभग 28 वर्षो के सेवाकाल के दौरान ना तो क्रमोन्नति वेतनमान सम्बन्धी लाभों की प्राप्ति हेतु विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण दायर कराया गया । उसकी सेवानिवृत्ति दिनक 29.02.2020 को हुई थी । उसके द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम रिट याचिका क्रमांक 17625/2021, दिनांक 04.09.2021 को दायर की गयी है । उपरोक्तानुसार सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष 07 माह पश्चात् रिट याचिका दायर की गई है ।

(ब) परिसीमा अधिनियम 1963 में में इस पृकृति के प्रकरणों में न्यायालयीन प्रकरण दायर करने की अधिकतम समय सीमा Cause Of Action उत्पन्न होने के उपरांत 03 वर्ष तक निर्धारित की गई है जबकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम रिट याचिका 16 वर्षो बाद दायर की गयी है –

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 के माध्यम से कार्यभारित वाहन

चालकों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के उपरांत दिनांक 19.04.1999 से नियमित स्थापना के कर्मचारियों के सामान दो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया था। डपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा प्रथम रिट याचिका क्रमांक 17625/2021 के माध्यम से चाहे गए लाभों के प्रावधान दिनांक 19.04.1999 से ही लागू हो गए थे। याचिकाकर्ता कर्मचारी की कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति दिनांक 18.06.1993 की है तथा उसके मामले में 12 वर्ष का सेवाकाल, यानि प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक 18.06.2005 को उत्पन्न हो चुकी थी । उक्तानुसार इस प्रकरण में Cause Of Action, वर्ष 2005 में ही उत्पन हो गया था, जब उसे प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया था। परिसीमा अधिनियम 1963 में में इस प्रकृति के प्रकरणों में न्यायालयीन प्रकरण दायर करने की अधिकतम समय सीमा Cause Of Action उत्पन्न होने के उपरांत 03 वर्ष तक निर्धारित की गई है । याचिकाकर्ता के मामले में Cause Of Action, दिनांक 18.06.2005 को उत्पन हो गया था, उक्तानुसार रिट याचिका अधिकतम वर्ष 2008 तक दायर की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी । प्रकरण में यदि Cause Of Action की दृष्टि से देखा जावे तो यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा Cause Of Action उत्पन्न होने के 16 वर्षो के बाद रिट पिटीशन क्र. 17625/2021, दिनांक 04.09.2021 को दायर की गयी है ।

(स) कार्यवाही का कारण मौजूद होते हुए भी अत्याधिक विलम्ब से रिट याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों को पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए :–

(i) याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा चाहे गए लाभ किसी सेवा नियम अथवा प्रशासकीय आदेश पर आधारित नहीं है। ये लाभ मान न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रकरण **''तेजूलाल यादव बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य [ILR (2009) MP 1326]''** एव **रिट याचिका क्रमांक 876/2015 (श्याम सुन्दर उपाध्याय एवं 15 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2015** का सहारा लिया गया है । इनमे से **''तेजूलाल यादव''** प्रकरण का निर्णय तो याचिकाकर्ता के मामले में **Cause Of Action** उत्पन्न होने के 04 वर्ष पश्चात् हो चुका था, तब भी उसके द्वारा न्यायालय की शरण नहीं ली गयी जबकि उसके पास इस निर्णय के पारित होने के काफी पूर्व से ही कार्यवाही का कारण मौजूद था । यदि याचिकाकर्ता के मामले पर अत्याधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया जावे तो भी उसे अधिकतम वर्ष 2009 में ही, जबकि **''तेजूलाल यादव सुप्रा''** निर्णय पारित हुआ था, वाद दायर कर देना चाहिए था । किन्तु उसने वर्ष 2009 एव वर्ष 2015 में अभिनिर्णित प्रकरणों का सहारा लेते हुए **क्रमोन्नति योजना** का लाभ प्राप्त करने के लिये **''तेजूलाल यादव सुप्रा''** एवं **''श्याम सुन्दर उपाध्याय सुप्रा''** निर्णय के 12 /06 वर्षो के उपरांत, परिपत्र दिनांक 29 मार्च 2001 जारी होने के 20 वर्षो पश्चात् एवं Cause Of Action उत्पन्न होने के 16 वर्षो के पश्चात रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन क्र. 17625/2021 में इस बाबत कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है कि उसने न्यायलय के समक्ष जाने में इतना बिलम्ब क्यों किया गया है?

(ii) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ जागरूक और सतर्क कर्मचारियों ने समय पर न्यायालयीन प्रकरण दायर करके कोई लाभ प्राप्त किया है तो ऐसे मामले में पारित निर्णय के आधार पर अन्य सोये हुए कर्मचारियों को जो Cause Of Action उत्पन्न होने के

कई वर्षो के पश्चात रिट याचिका दायर करते है, वह लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कुछ न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :–

(a) In State of Karnataka & Ors. Vs. S.M. Kotrayya & Ors., (1996) 6 SCC 267, the Hon'ble Supreme Court rejected the contention that a petition

should be considered ignoring the delay and laches on the ground that he filed the petition just after coming to know of the relief granted by the Court in a similar case as the same cannot furnish a proper explanation for delay and laches. The Court observed that such a plea is wholly unjustified and cannot furnish any ground for ignoring delay and laches.

(b) Same view has been reiterated by the Hon'ble Supreme Court in Jagdish Lal & Ors. Vs. State of Haryana & Ors., AIR 1997 SC 2366, observing as under:-

> "Suffice it to state that appellants may be sleeping over their rights for long and elected to wake-up when they had impetus from Veerpal Chauhan and Ajit Singh's ratio.... desperate attempts of the appellants to re-do the seniority, held by them in various cadre.... are not amenable to the judicial review at this belated stage. The High Court, therefore, has rightly dismissed the writ petition on the ground of delay as well."

(c) In M/s. Roop Diamonds & Ors. Vs. Union of India & Ors., AIR 1989 SC 674, the Hon'ble Supreme Court considered a case where petitioner wanted to get the relief on the basis of the judgment of the Supreme Court wherein a particular law had been declared ultra vires. The Court rejected the petition on the ground of delay and latches observing as under: -

> "There is one more ground which basically sets the present case apart. Petitioners are re-agitating claims which they have not persued for several years. Petitioners were not vigilant but were content to be dormant and closeto sit on the fence till somebody else's case came to be decided."

(ii) स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी **''तेजूलाल यादव सुप्रा''** एवं **''श्याम सुन्दर उपाध्याय सुप्रा''** प्रकरण में पारित निर्णयों का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखता है ।

(द) याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गयी रिट याचिका विलम्ब और अवधि बीत जाने जैसे दोषो से ग्रसित है तथा याचिका के माध्यम से प्रस्तुत दावा मेरिट के आधार पर विचारणीय ही नहीं है–

प्रकरण में यदि Cause Of Action को आधार बनाया जाये तो याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा Cause Of Action उत्पन्न होने के 16 वर्षो उपरांत रिट याचिका दायर की गयी है।

उक्तानुसार कारित विलम्ब न्यायालयीन कार्यवाहियों के मामले में अत्याधिक विलम्ब के रूप में गिना जाता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा द्वारा अपने अनेको न्यायदृष्टांतो के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब किसी भी प्रकरण की मेरिट तथा याचिकाकर्ता के अधिकारों को समाप्त कर देता है । उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता कर्मचारी का दावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायदृष्टान्तों के आधार पर विलंब एवं अवधि बीत जाने के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **विलम्ब एवं अवधि बीत जाने से** सम्बंधित कुछ न्यायदृष्टान्त निम्नानुसार हैः–

(i) In State of Maharastra v. Digambar reported in AIR 1995 SC 1991, the Honble Supreme Court held as follows:

> 12. How a person who alleges against the State of deprivation of his legal right, can get relief of compensation from the State invoking writ jurisdiction of the High Court under article 226 of the Constitution even though, he is guilty of laches or undue delay is difficult to comprehend, when it is well settled by decision of this Court that no person, be he a citizen or otherwise, is entitled to obtain the equitable relief under Article 226 of the Constitution if his conduct is blame- worthy because of laches, undue delay, acquiescence, waiver and the like.
>
> Moreover, how a citizen claiming discretionary relief under Article 226 of the Constitution against a State, could be relieved of his obligation to establish his blameworthy conduct for getting such relief, where the State against which relief is sought is a welfare State, is also difficult to comprehend. Where the relief sought under Article 226 of the Constitution by a person against the welfare State is founded on its alleged illegal or wrongful executive action, the need to explain laches or undue delay on his part to obtain such relief, should, if anything, be more stringent than in other cases, for the reason that the State due to laches or undue delay on the part of the person seeking relief, may not be able to show that the executive action complained of was legal or correct for want of records pertaining to the action or for the officers who were responsible for such action not being available later on.
>
> Further, where granting of relief is claimed against the State on alleged unwarranted executive action, is bound to result

> in loss to the public exchequer of the State or in damage to other public interest, the High Court before granting such relief is required to satisfy itself that the delay or laches on the part of a citizen or any other person in approaching for relief under Article 226 of the Constitution on the alleged violation of his legal right, was wholly justified in the facts and circumstances, instead of ignoring the same or leniently considering it.
>
> Thus, in our view, persons seeking relief against the State under Article 226 of the Constitution, be they citizens or otherwise, cannot get discretionary relief obtainable thereunder unless they fully satisfy the High Court that the facts and circumstances of the case clearly justified the laches or undue delay on their part in approaching the Court for grant of such discretionary relief. Therefore, where a High Court grants relief to a citizen or any other person under Article 226 of the Constitution against any person including the State without considering his blame-worthy conduct, such as laches or undue delay, acquiescence or waiver, the relief so granted becomes unsustainable even if the relief was granted in respect of alleged deprivation of his legal right by the State.

(ii) The Apex Court in S.S. Balu vs. State of Kerala (2009) 2 SCC 479 in the following terms:

> "17. It is also well-settled principle of law that "delay defeats equity". The Government Order was issued on 15-1-2002. The appellants did not file any writ application questioning the legality and validity thereof. Only after the writ petitions filed by others were allowed and the State of Kerala preferred an appeal there against, they impleaded themselves as party-respondents.
>
> It is now a trite law that where the writ petitioner approaches the High Court after a long delay, reliefs prayed for may be denied to them on the ground of delay and laches irrespective of the fact that they are similarly situated to the other candidates who obtain the benefit of the judgment. It is, thus, not possible for us to issue any direction to the State of Kerala or the Commission to appoint the appellants at this stage."

(iii) In Board of Secondary Education of Assam v. Mohd. Sarifuz Zaman, reported in (2003) 12 SCC 408, the Apex Court has observed as follows:

> 12. Delay defeats discretion and loss of limitation destroys the remedy itself. Delay amounting to laches results in benefit of discretionary power being denied on principles of equity. Loss of limitation resulting into depriving of the remedy, is a principle based on public policy and utility and not equity alone.

(iv) In Virender Chaudhary v. Bharat Petroleum Corporation reported in 2009 (1) SCC 297, the Apex Court held that the court exercises its jurisdiction only upon satisfying itself that it would be equitable to do so and also observed that Delay/ Latches, indisputably, are the relevant factors. The Court held thus:

> 15. The Superior Courts, times without number, applied the equitable principles for not granting a relief and/or a limited relief in favour of the applicant in a case of this nature. While doing so, the court although not oblivious of the fact that no period of limitation is provided for filing a writ petition but emphasize is laid that it should be filed within a reasonable time. A discretionary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India need not be exercised if the writ petitioner is guilty of delay and latches.

(v) In Veerayeeammal v. Seeniammal reported in 2002 (1) SCC 134, at Paragraph 13, is extracted here under:

> 13. The word reasonable has in law prima facie meaning of reasonable in regard to those circumstances of which the person concerned is called upon to act reasonably knows or ought to know as to what was reasonable. It may be unreasonable to give an exact definition of the word reasonable. The reason varies in its conclusion according to idiosyncrasy of the individual and the time and circumstances in which he thinks. The dictionary meaning of the reasonable time is to be so much time as is necessary, under the circumstances, to do conveniently what the contract or duty requires should be done in a particular case. In other words it means, as soon as circumstances permit.

(vi) In Chennai Metropolitan Water Supply & Sewerage Board v. T. T. Murali Babu 2014 (4) SCC 108, the Apex Court held as follows:

Thus, the doctrine of delay and laches should not be lightly brushed aside. A writ court is required to weigh the explanation offered and the acceptability of the same. The court should bear in mind that it is exercising an extraordinary and equitable jurisdiction. As a constitutional court it has a duty to protect the rights of the citizens but simultaneously it is to keep itself alive to the primary principle that when an aggrieved person, without adequate reason, approaches the court at his own leisure or pleasure, the Court would be under legal obligation to scrutinize whether the list at a belated stage should be entertained or not.

Be it noted, delay comes in the way of equity. In certain circumstances delay and laches may not be fatal but in most circumstances inordinate delay would only invite disaster for the litigant who knocks at the doors of the Court. Delay reflects inactivity and inaction on the part of a litigant a litigant who has forgotten the basic norms, namely, procrastination is the greatest thief of time and second, law does not permit one to sleep and rise like a phoenix.

Delay does bring in hazard and causes injury to the lis. In the case at hand, though there has been four years delay in approaching the court, yet the writ court chose not to address the same. It is the duty of the court to scrutinize whether such enormous delay is to be ignored without any justification. That apart, in the present case, such belated approach gains more significance as the respondent-employee being absolutely careless to his duty and nurturing a lackadaisical attitude to the responsibility had remained unauthorisedly absent on the pretext of some kind of ill health. We repeat at the cost of repetition that remaining innocuously oblivious to such delay does not foster the cause of justice.

On the contrary, it brings in injustice, for it is likely to affect others. Such delay may have impact on others ripened rights and may unnecessarily drag others into litigation which in acceptable realm of probability, may have been treated to have attained finality. A court is not expected to give indulgence to such indolent persons who compete with Kumbhakarna or for that matter Rip Van Winkle. In our considered opinion, such delay does not deserve any

> indulgence and on the said ground alone the writ court should have thrown the petition overboard at the very threshold.

(vii) In Prabhakar v. Joint Director, Sericulture Department reported in 2015 (3) SCC 1, the Apex Court held as follows:

> 37. Let us examine the matter from another aspect viz. laches and delays and acquiescence.
>
> 38. It is now a well-recognised principle of jurisprudence that a right not exercised for a long time is non-existent. Even when there is no limitation period prescribed by any statute relating to certain proceedings, in such cases courts have coined the doctrine of laches and delays as well as doctrine of acquiescence and non-suited the litigants who approached the Court belatedly without any justifiable explanation for bringing the action after unreasonable delay. Doctrine of laches is in fact an application of maxim of equity delay defeats equities.

(इ) यदि दावों का सम्बंन्ध पेंशन सम्बन्धी लाभों से होने के आधार पर Continuous Cause Of Action मानते हुए Delay और Latches की उपेक्षा भी कर दी जावे तो अत्याधिक विलम्ब से तथा Cause Of Action उत्पन्न होने के कई वर्षों बाद दायर रिट याचिका मौन सहमति– स्वीकृति (Acquiescence) के आधार पर भी अमान्य किये जाने योग्य है:–

यदि प्रकरण मे पेंशन लाभों को आधार बनाकर **Delay** और **Latches** की उपेक्षा भी कर दी जावे तो 16 वर्षों बाद दायर रिट याचिका मौन सहमति– स्वीकृति **(Acquiescence)** के आधार पर भी अमान्य किये जाने योग्य है। याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा अपने कार्यभारित स्थापना के पूरे लगभग 28 वर्षो के सेवाकाल के दौरान ना तो क्रमोन्नति वेतनमान सम्बन्धी लाभों की प्राप्ति हेतु विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण दायर कराया गया । रिट याचिका के माध्यम से चाहे गए लाभों को प्राप्त नहीं करने के बारे में पूरे सेवाकाल के दौरान और यहाँ तक की सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष 07 माह पश्चात् तक भी उसकी मौन सहमति– स्वीकृति **(Acquiescence)** रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेक न्याय दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मौन सहमति– स्वीकृति **(Acquiescence)** वस्तुतः व्यक्ति के अधिकारों को नष्ट कर देती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 8223/2009 (चेयरमेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम.जे.जेम्स) में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2021** में निम्नानुसार कहा गया है :–

> 28**. ……**If at all, in such cases, the delay furnishes a cause of action, which in some cases as elucidated in Union of India and Others v. Tarsem Singh2008 (8) SCC 648, may be continuing cause of

action. The State being a virtuous litigant should meet the genuine claims and not deny them for want of action on their part. However, this general principle would not apply when, on consideration of the facts, the court concludes that the respondent had abandoned his rights, which may be either express or implied from his conduct. Abandonment implies intentional act to acknowledge, as has been held in paragraph 6 of Motilal Padampat Sugar Mills Co. Ltd. v. State of Uttar Pradesh and Others1979 (2) SCC 409. Applying this principle of acquiescence to the precept of delay and laches, this Court in U.P. Jal Nigam and Another v. Jaswant Singh and Another 2006 (11) SCC 464, after referring to several judgments, has accepted the following elucidation in Halsbury's Laws of England:

> "12. The statement of law has also been summarised in Halsbury's Laws of England, para 911, p. 395 as follows:
>
> "In determining whether there has been such delay as to amount to laches, the chief points to be considered are:
>
> (i) acquiescence on the claimant's part; and
>
> (ii) any change of position that has occurred on the defendant's part.
>
> Acquiescence in this sense does not mean standing by while the violation of a right is in progress, but assent after the violation has been completed and the claimant has become aware of it. It is unjust to give the claimant a remedy where, by his conduct, he has done that which might fairly be regarded as equivalent to a waiver of it; or where by his conduct and neglect, though not waiving the remedy, he has put the other party in a position in which it would not be reasonable to place him if the remedy were afterwards to be asserted. In such cases lapse of time and delay are most material. Upon these considerations rests the doctrine of laches."
>
> 13. In view of the statement of law as summarised above, the respondents are guilty since the respondents have acquiesced in accepting the retirement and did not challenge the same in time. If they would have been vigilant enough, they could have filed writ petitions as others did in the matter. Therefore, whenever it appears that the claimants lost time or whiled it away and did not rise to the occasion in time for filing the writ petitions, then in such cases, the court should be very slow in granting the relief to the incumbent. Secondly, it has also to be taken into

consideration the question of acquiescence or waiver on the part of the incumbent whether other parties are going to be prejudiced if the relief is granted. In the present case, if the respondents would have challenged their retirement being violative of the provisions of the Act, perhaps the Nigam could have taken appropriate steps to raise funds so as to meet the liability but by not asserting their rights the respondents have allowed time to pass and after a lapse of couple of years, they have filed writ petitions claiming the benefit for two years. That will definitely require the Nigam to raise funds which is going to have serious financial repercussions on the financial management of the Nigam.

Why should the court come to the rescue of such persons when they themselves are guilty of waiver and acquiescence?"

(फ) याचिकाकर्ता का प्रकरण "Continuons Wrong" की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है तथा एक पालिसी को पूर्णतः स्वीकार कर लेने के कई वर्षो बाद दूसरी पालिसी की मांग न्यायोचित नहीं हैः–

(i) यदि इस प्रकरण को याचिकाकर्ता कर्मचारी को हो रहे पेंशन राशि के नुकसान के मद्देनजर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत "Continuons Wrong" के दृष्टिकोण से भी देखा जाये, तो यह पाया जाता है कि म.प्र.शासन वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से, वर्ष 2008 में नियमित कर्मचारियों को दिये गये समयमान वेतनमान के लाभ को कार्यभारित कर्मचारियों हेतु लागू कर दिया गया था। **याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारी को रिट याचिका के माध्यम से चाहे गए प्रथम और द्वितीय उच्चतर वेतनमानों का लाभ मुख्य अभियंता इंदौर द्वारा आदेश क्रमांक 147 दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से स्वीकृत कर, दिनांक 01.01.2016 से प्रदान कर दिए गए हैं**। उपरोक्तानुसार स्थिति के दृष्टिगत यह प्रकरण "Continuons Wrong" की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है।

(ii) यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी ने उसके लिये वर्ष 2016 में लागू की गई पॉलिसी **{म.प्र.शासन वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016}** का लाभ लेते समय अथवा पॉलिसी लागू करने के दिनांक से वर्तमान रिट याचिका दायर करने के दिनांक तक, उक्त पॉलिसी के विरोध में कोई बात नहीं कही है तथा उक्त पॉलिसी को पूर्णतः स्वीकार किया है। पॉलिसी को स्वीकार करने एवं उसका लाभ लेने के 05 वर्षो पश्चात, इस तरह के लाभ पूर्व के दिनांकों से प्राप्त करने हेतु रिट याचिका दायर करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

(य) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व देय दिनांकों से क्रमोन्नती/समयमान वेतनमान योजना का लाभ चाहने वाले न्यायालयीन प्रकरणों को विलंब एवं अवधि बीत जाने के आधार पर खारिज किया गया हैः–

(i) रिट याचिका क्रमांक 5382/2023 (मुलसिंग उमठ बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में याचिकाकर्ता कर्मचारी को द्वितीय क्रमोन्नती का लाभ दिनांक 23.08.2006 से दिया गया था जबकि यह उसे दिनांक 19.04.1999

से प्राप्त होना था। माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वर्ष 1999 में देय लाभ के लिए याचिकाकर्ता 25 वर्षो के बाद न्यायालय में आया है जबकि उसके द्वारा विलंब के लिये कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पुराने एवं मृत दावों को पुनः खोला नही जा सकता है। याचिकाकर्ता अपने अधिकारों पर 25 वर्षों से सो रहा था । याचिका को विलंब एवं अवधि बीत जाने के आधार पर खारिज किया जाता है। पारित निर्णय दिनांक 03.03.2023 निम्नानुसार है :–

2. By way of this present under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner has not challenged any specific order, but seeking a direction to grant second Krammonati pay scale on completion of 24 years of service w.e.f. 19.04.1999.

3. Initially, the petitioner was appointed on the post of Assistant Teacher vide order dated 05.11.1973 by the respondent No.2. It is submitted by the learned counsel for the petitionr that the Principal, C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Narsinghgarh, District Rajgarh has wrote a letter to respondent No.2 for grant of Second Krammonati to the petitioner from 19.04.1999 as he has been granted the benefits from 23.08.2006. It is submitted that despite of specific direction issued from the State Government regarding grant of Kramonnati pay scale to the employees after completion of their prescribed service tenure, the petitioner is being deprived of the same, thereby the principles of natural justice stand violated.

4. On the other hand, learned counsel for the State, on advance notice, has vehemently opposed the prayer and raised a preliminary objection with regard to delay and latches. He submitted that the petitioner in Para - 4 of the memo of petition has not explained the delay for not approaching this Court for the last 25 years and has been maintaining silence. In such circumstances, the petitioner suffers from inordinate delay and latches, therefore, the same is liableto be dismissed.

……

……

7. The petitioner has approached this Court after 25 long years, for which no plausible explanation has been put forth by him. Stale and dead cases can not be reopened. The petitioner has been sleeping over his right and woke up after a long period of 25 years to approach this Court. In view of the above, this Court refrains from exercising extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India as the petition suffers from unexplained delay and laches on the part of the petitioner.

8. Accordingly, the petition stands dismissed on the ground of delay and laches.

(ii) रिट याचिका क्रमांक 14203/2023 (श्रीमति राधा ठाकरिया बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में याचिकाकर्ता कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा उपरांत देय तृतीय समयमान वेतनमान, जो म.प्र.शासन वित विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2014 पर आधारित था, प्राप्त नहीं हुआ था। कर्मचारी द्वारा दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त होने के बाद वर्ष 2023 में इसे प्राप्त करने हेतु रिट याचिका दायर की गई थी। इस प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई थी कि मामला वेतन निर्धारण और पेंशन से संबंधित होने के कारण विलंब के बावजूद कर्मचारी को लाभ प्रदाय किया जाना चाहिए। किंतु माननीय न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रकरणों क्रमशः (1) **Karnataka Power Corpon. Ltd. Vs. K. Thangappan** reported **in (2006) 4 SCC 322**, (2)M.P. Ram Mohan Raja Vs. State of T.N. Reported in (2007) 9 SCC 78,(3)Shiv Dass Vs. Union of India reported in (2007) 9 SCC 274,(4)Nadia Distt. Primary School Council Vs. Sristidhar Biswar reported in (2007) 12 SCC 779,(5)U.P. Jal Nigam Vs. Jaswant Singh reported in (2006) 11 SCC 464,(6)Jagdish Lal Vs. State of Haryana reported in (1997) 6 SCC 538,(7)NDMC Vs. Pan Singh reported in (2007) 9 SCC 278,(8)State of Orissa v. Pyarimohan Samantaray reported in (1977) 3 SCC 396,(9)State of Orissa v. Arun Kumar Patnaik reported in (1976) 3 SCC 579,(10)BSNL v. Ghanshyam Dass reported in (2011) 4 SCC 374,(11)Ghulam Rasool Lone v. State of J&K reported in (2009) 15 SCC 321,(12) P.S. Sadasivaswamy v. State of T.N., reported in (1975) 1 SCC 152,(13)Administrator of Union Territory of Daman and Diu and others v. R.D. Valand reported in 1995 Supp (4) 593 एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा W.P.No.17493/2022 (Ratiram Dohare vs. The State of M.P. and others) में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 का हवाला देते हुए दावे को खारिज कर दिया कि यदि कोई कर्मचारी फेंस सिटर हो तथा अपने अधिकारों पर सालों से सो रहा हो तो ऐसे लाभ को देने से मना किया जा सकता है क्योकिं वेतन एरियर की रिकवरी हेतु परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 7 में 03 वर्ष की अवधि की समय–सीमा दी गई है। वर्तमान याचिका सेवानिवृत्ति के 8 वर्षो के बाद एवं परिपत्र दिनांक 30.09.2014 के माध्यम से योजना लागू होने के 09 वर्षो के बाद दायर की गई है तथा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मौजूद नही है कि याचिकाकर्ता पूर्व में न्यायालय की शरण में क्यों नहीं आया। निर्णय दिनांक 20.07.2023 निम्नानुसार हैः–

7. At this stage, it is submitted by the counsel for the petitioner that since the petitioner had already completed her 30 years of service in the year 2004, therefore, she may be granted 3rd Time Pay Scale with effect from 01.07.2014 i.e the date from which the circular dated 30.09.2014 was made applicable.

8. It is fairly conceded by the counsel for the petitioner that the petitioner has retired on 30.06.2015. The present petition has been filed in the year 2023.

9. It is submitted by the counsel for the petitioner that where an issue relates to fixation of pay or pension, the relief may be granted in spite of delay as it does not affect the right of the third person.

10. Considered the submissions made by the counsel for the petitioner.

11. The petitioner is right in submitting that where the fixation of pay or pension, does not affect the right of a third person, then generally the delay should not be pressed into service to dismiss the petition. However, where a person was a fence sitter or was sleeping over hisright for years together, then the equitable relief can be denied specifically when the period of limitation provided for recovery of wages is three years as per Article 7 of the Limitation Act.

12. The present petition has been filed after eight years of her retirement and after nine years of introduction of scheme of circular dated 30.09.2014. No explanation whatsoever has been given by the petitioner for not approaching this Court at the earliest.

---

27. Accordingly, this Court is of the considered opinion that since the petitioner has not given any explanation at all for delay in filing the petition and although no period of limitation applies to writ petition but when a specific provision has been made under the Limitation Act for recovery of wages, then this Court can always take the said aspect into consideration for guidance purposes.

28. Accordingly, the petition fails and is hereby dismissed.

(iii) रिट याचिका क्रमांक 35989/2024 (के पी पटेल बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में याचिकाकर्ता कर्मचारी को 28 वर्ष की सेवा उपरांत देय तृतीय समयमान वेतनमान, जो म.प्र.शासन वित विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 एवं परिपत्र दिनांक 18.07.2008 पर आधारित था, प्राप्त नहीं हुआ था। कर्मचारी द्वारा दिनांक 30.06.2009 को सेवानिवृत्त होने के बाद वर्ष 2024 में इसे प्राप्त करने हेतु रिट याचिका दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रकरणों क्रमशः (1) **State of Orissa & Anr. Mamta Mohanty reported in (2011) 3 SCC 436**, (2) **Karnataka Power Corpon. Ltd. Vs. K. Thangappan** reported **in (2006) 4 SCC 322**,(3) **Ashok kumar vs District Magistrate , Basti reported in (2012) 3 SCC 311**, एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णित प्रकरण **(M/S) Focus Energy Ltd Vs. Governmnt of India reported in I.L.R. (2011) M.P. 53** का हवाला देते हुए यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अपने अधिकारों पर 15 वर्षो तक सोता रहा है तथा वह न्यायालय के समक्ष आने में किये गए विलम्ब को स्पष्ट करने में असफल रहा है । निर्णय दिनांक 21.01.2025 निम्नानुसार हैः–

2. It is the case of the petitioner that he initially entered into service in the respondent/department on the post of Assistant Engineer on 17.04.1971. He

stood retired on attaining the age of superannuation on 30.06.2009. He has completed 34 years of regular service in the respondent/department. A circular has been issued by the Finance Department of the State Government dated 24.01.2008 for extending the benefit of higher pay scale in the light of Fundamental Rule 22(D) and rule 22(A)(ii), if the employee is not promoted. Another circular dated 18.07.2008 has been issued by the Finance Department wherein the pay scale of Sub Engineer has been fixed by 1st higher pay scale after completion of 10 years, 2nd higher pay scale after completion of 20 years of service and 3rd higher pay scale after completion of 30 years of service. The petitioner approached the authorities requesting for extending the said benefit, but of no consequence. Thereafter, the petitioner retired from service on 30.06.2009. Thereafter, this petition has been filed seeking a direction to the authorities to comply with comply with the aforesaid circulars and extend the benefit.

……..

……..

9. If the aforesaid judgements are applied to the facts of the present it is clear that the petitioner has slept over is right for a considerable period of almost 15 years and the delay has not been explained by the petitioner. No judgment is placed before this Court to substantiate the arguments of delay in approaching this Court.

10. Under these circumstances, no relief can be extended to the petitioner. The petition sans merit and is accordingly dismissed.

(iv) उपर उल्लेखित तीनो प्रकरणों एवं याचिकाकर्ता कर्मचारी के मामले में बहुत अधिक समानताये मौजूद है इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत दावे को मान्य नहीं किया जा सकता है ।

(र) यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के कार्यभारित कर्मचारियों को उनके प्रकरण में विलम्ब एवं अवधि बीत जाने पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण प्राप्त हुये है तो इस आधार पर याचिकाकर्ता कर्मचारी को भी क्रमोंन्नति वेतनमान योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **''इंडियन काउंसिंल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य'' [(1997) (6) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को जानकारी के आभाव में कोई लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गये समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(6) उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन क्रमांक 17625/2021 (साबिर खान बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास के अधिनस्थ कार्यरत रहे श्री साबिर खान, सेवानिवृत्त कार्यभारित टेलीफोन अटेंडेंट द्वारा चाहे गए 12 वर्ष एवं 24 वर्षो की सेवा उपरांत, प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ को उपर उल्लेखित तथ्यों एवं न्यायदृष्टांतों के आधार पर विलम्ब, अवधि बीत जाने और मौन सहमति– स्वीकृति (Acquiescence) की दृष्टि से अनुपयुक्त पाते हुए, अमान्य किया जाता है।

(7) यदि याचिकाकर्ता श्री साबिर खान, सेवानिवृत्त कार्यभारित टेलीफोन अटेंडेंट इस निराकरण से असंतुष्ट हों तो वे अपनी अपील 02 माह के भीतर प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

मुख्य अभियंता

पृ.क्र. /मु.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2025 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, उज्जैन मण्डल, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।
(3) अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, जल भवन,बाणगंगा ,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।
(4) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग खंड देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।
(3) श्री साबिर खान पिता नूर मोहम्मद खान, सेवानिवृत्त सिया पुरा देवास (म.प्र.) की ओर प्रेषित।

मुख्य अभियंता